मज़हर हसन

बनाम

गंगू सिंह एवं अन्य

(सी.ए. सं. 2008 का 186)

9 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और अफताब आलम, जे.जे.]

भूमि सुधारः

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम - धारा 209 और 210 - यू.पी.जेड.ए और एलआर अधिनियम की धारा 209 के तहत मुकदमे में प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली का डिक्री निष्पादन आवेदन समय बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया। डिक्री धारकों ने विवादित भूमि को अपीलकर्ता को बेचा जिसने भूमि को अपने नाम पर परिवर्तित कर लिया। धारा 9ए(2) के तहत उत्तरदाताओं द्वारा आपत्ति। उ.प्र. समेकन प्रतिकूल कब्जे के आधार पर होल्डिंग्स अधिनियम के उत्परिवर्तन और स्वामित्व के दावे के लिए चकबंदी अधिकारी द्वारा आपत्ति खारिज कर दी गई। लेकिन निपटान अधिकारी द्वारा अपील में बरकरार रखा गया। उप निदेशक ने निपटान अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की

जिसने आदेश को पुनः स्थापित कर दिया ई-सेटलमेंट अधिकारी-अपील पर, आयोजित: चकबंदी अधिकारी का यह निष्कर्ष कि उत्तरदाता 12 वर्षों तक अपना निरंतर कब्जा साबित करने में असमर्थ रहे और इसके विपरीत अपीलकर्ता का कब्जा था, निर्णायक था। उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को नजरअंदाज करने और यह मानने में गलती की कि उत्तरदाता 12 वर्षों तक अपना निरंतर कब्जा साबित करने में असमर्थ रहे। केवल कब्जा इसलिए माना जाएगा क्योंकि निष्पादन आवेदन को समय बाधित के रूप में खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की याचिका पर उचित विचार न करके गलती की कि उत्तरदाताओं ने स्वेच्छा से डिक्री धारकों को कब्जा सौंप दिया था और इस कारण से डिक्री का निष्पादन नहीं किया गया था। समय पर -उत्तर प्रदेश जोत समेकन अधिनियम - धारा 9ए(2) - भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226 - प्रतिकूल कब्ज़ा।

विवादित भूमि उत्तर प्रदेश राज्य के एक गाँव में स्थित थी। उक्त भूमि के संबंध में, 'आर' और उसकी बहनों, मूल किरायेदार के उत्तराधिकारी, ने कायर्वाही कर यू.पी.जेड.ए. की धारा 209 एवं एल.आर. अधिनियम के तहत दायर एक मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ बेदखली का डिक्री प्राप्त की। द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि की गई। डिक्री धारक 'आर' और उसकी बहनों ने एक निष्पादन आवेदन दायर किया, जिसे हालांकि, समय बाधित होने के कारण खारिज

कर दिया गया। इसके बाद, 'आर' और उसकी बहनों ने विवादित भूमि अपीलकर्ता को बेच दी, जिसने बिक्री विलेख के आधार पर, राजस्व अभिलेखों में उनका नाम परिवर्तित कर दिया।

इस बीच, गांव में चकबंदी अभियान शुरू हो गया और उत्तरदाताओं ने विवादित भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए अपीलकर्ता का नाम हटाने और उसके स्थान पर अपना नाम दर्ज करने के लिए यूपी चकबंदी अधिनियम की धारा 9-ए (2) के तहत आपत्ति दर्ज कराई। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर, चकबंदी अधिकारी द्वारा आपत्ति को खारिज कर दिया गया था, लेकिन निपटान अधिकारी द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था, जिन्होंने माना था कि प्रतिवादियों ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से विवादित भूमि पर सिरदारी अधिकार प्राप्त कर लिया था। उपसंचालक चकबंदी ने बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया। प्रतिवादियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की जिसने निपटान अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया।

इसलिए वर्तमान अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

1.1. यू.पी.जेड.ए की धारा 210 एवं एल.आर. अधिनियम के संदर्भ में दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला - उसे निर्धारित सीमा अवधि के भीतर डिक्री को निष्पादित करने में विफल रहना चाहिए और दूसरा

व्यक्ति (दावा करने वाला प्रतिकूल अधिकार) को विवादित भूमि का कब्जा लेना या बनाए रखना चाहिए। कानून की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से उत्तरदाताओं के पक्ष में निर्णय दिया। इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि डिक्री धारकों 'आर' और उनकी बहनों द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को खारिज कर दिया गया था सीमा द्वारा वर्जित होने के रूप में। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि डिक्री की पुष्टि के बाद उच्च न्यायालय द्वारा, निर्णय-देनदार (उत्तरदाता) स्वेच्छा से विवादित का कब्जा सौंप दिया था, डिक्री धारकों और निष्पादन के उद्देश्य के लिए भूखंड पूरा हुआ और यही कारण था कि डिक्री समय पर निष्पादन में नहीं रखा गया था और अनुमति दी गई थी समय बाधित हो गया, उच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया। अपीलार्थी द्वारा उठाई गई याचिका पर विचार करना। [पैरा-5,6] [409-ई,एफ; 410-ए, बी, सी; 411-ए, बी]

1.2. चकबन्दी अधिकारी का आदेश पूर्णतया विवादित भूखंडों पर प्रतिद्वंदी पक्षों के कब्जे के मुद्दे पर आधारित है। यह मुद्दा न केवल चकबंदी अधिकारियों के समक्ष उठाया गया बल्कि यह विवाद की जड़ बन गया। दोनों पक्षों ने इस पर कब्जे के अपने दावे के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये। विवादित भूखंड और चकबंदी अधिकारी ने अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि प्रतिवादी 12 वर्षों तक विवादित भूमि पर अपना निरंतर कब्जा साबित

करने में असमर्थ रहे और इसके विपरीत अपीलकर्ता ही था। विवादित भूखंडों पर ई का कब्जा था। चकबंदी अधिकारी द्वारा दर्ज कब्जे का निष्कर्ष विवाद के लिए निर्णायक था और उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को नजरअंदाज करने में गलती की और यह माना कि उत्तरदाताओं को केवल इसलिए कब्जा माना जाएगा क्योंकि 'आर' और अन्य डिक्री द्वारा निष्पादन आवेदन दायर किया गया था। धारकों को समयबाधित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। तद्नुसार उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाता है और उप निदेशक चकबंदी एवं चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश को बहाल किया जाता है। [पैरा 6, 7] [411-बी, सी, डी; 412-सी, डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 186/2008।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायिक सी.एम.डब्ल्यू.पी. सं. 3620/1979 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 20.7.2005 से।

एच.सी. खरबंदा, ए.के. शर्मा और एम.पी. शोरावाला अपीलार्थी।

धीरज.के. अग्रवाल, आशा तनेजा और मृदुला रे भारद्वाज उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अफताब आलम, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील सिविल विविध रिट याचिका संख्या 3620/1979 (रिट याचिका संख्या 4216/1979 से संबंधित) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 जुलाई 2005 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। आक्षेपित आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय ने उप निदेशक चकबंदी और चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के आदेश को बहाल कर दिया। बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी के आदेश, दिनांक 12 सितंबर, 1978 ने, बदले में, चकबंदी अधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया था और भूमि के विवादित टुकड़ों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में उत्तरदाताओं के नाम दर्ज करने का निर्देश दिया था। विवाद उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित ग्राम धामपुर जिला बिजनौर में भूखंड संख्या 960/1, 971/1, 973/1, 982/2, 988/1, 989, 1008/2, 1010/1, 1010/2, 1011 और 1013 से संबंधित है।

3. भौतिक तथ्य इस प्रकार पढ़े और कहे जा सकते हैं। एक हेतराम विवादित भूखंडों का मूल खातेदार था। उनकी उत्तराधिकारी श्रीमती राम मूर्ति देवी और उनकी चार बहनें यू.पी.जेड.ए की धारा 209 के तहत उनके द्वारा दायर एक मुकदमे (मुकदमा संख्या 161) में उत्तरदाताओं के खिलाफ बेदखली का डिक्री प्राप्त करने में सक्षम थीं एवं एल.आर.एक्ट. जहां तक विवादित भूखंडों का सवाल है, डिक्री की पुष्टि उच्च न्यायालय में दूसरी अपील और पार्टियों द्वारा दायर क्रॉस अपील में की गई थी। डिक्री धारकों ने 21 मई, 1965 को एक निष्पादन आवेदन दायर किया, जिसे

निष्पादन मामला संख्या 21/69 के रूप में दर्ज किया गया था। हालाँकि, आवेदन को 26 जुलाई, 1969 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था क्योंकि डिक्री को सीमा अवधि से परे निष्पादित किया गया था। उनके निष्पादन आवेदन की अस्वीकृति के बाद, श्रीमती राम मूर्ति देवी और अन्य ने 13 अप्रैल, 1970 को कई भूखंडों का विक्रय पत्र निष्पादित किया। अली हसन (वर्तमान अपीलकर्ता के मृत पिता) के पक्ष में विवादित भूखंड शामिल हैं। विक्रय पत्र के आधार पर, अली हसन एकपक्षीय आदेश द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना नाम परिवर्तित कराने में सक्षम था। बाद में इस संबंध में अली हसन और प्रतिवादियों के बीच विवाद होने लगा। विवादित भूखंडों पर कब्जा कर लिया और विवाद ने सीआरपीसी की धारा 145 और 146 के तहत कार्यवाही को जन्म दिया। वे कार्यवाहियाँ 11 सितंबर, 1972 के आदेश द्वारा समाप्त की गईं, जिसके द्वारा विवादित भूखंडों को उत्तरदाताओं के पक्ष में जारी कर दिया गया।

4. इस बीच, गांव में चकबंदी की कार्यवाही शुरू हो गई और उत्तरदाताओं ने अली हसन का नाम हटाने और उसके स्थान पर अपना नाम दर्ज करने के लिए यूपी चकबंदी अधिनियम की धारा 9-ए (2) के तहत आपत्ति दर्ज कराई और दावा किया हे प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विवादित भूमि का स्वामित्व। चकबंदी अधिकारी ने 5 जुलाई, 1978 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्होंने प्रतिकूल कब्जे से विवादित भूखंडों पर सिरदारी

अधिकार हासिल नहीं किया है। चकबंदी अधिकारी के आदेश के खिलाफ, उत्तरदाताओं ने एक अपील दायर की, जिसे निपटान अधिकारी चकबंदी ने 12 जुलाई, 1978 के आदेश द्वारा अनुमति दी थी। निपटान अधिकारी ने माना और पाया कि याचिकाकर्ताओं ने विवाद में भूमि पर सिरदारी अधिकार हासिल कर लिया है। श्रीमती राम मूर्ति देवी और अन्य डिक्री धारकों द्वारा दायर निष्पादन मामले के रूप में प्रतिकूल कब्जे को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया गया था। बंदोबस्त अधिकारी के आदेश से दुखी होकर, श्रीमती राम मूर्ति देवी और उनकी बहनों और अली हसन दोनों ने चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष अलग-अलग संशोधन दायर किए, जिन्होंने 18 जनवरी, 1979 के एक सामान्य आदेश द्वारा संशोधन की अनुमति दी और आदेश को रद्द कर दिया। बंदोबस्त अधिकारी का, इसके बाद उत्तरदाताओं ने दो संशोधनों से उत्पन्न दो रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय का रुख किया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिट याचिकाओं को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी; उप संचालक चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों को निरस्त कर दिया गया तथा बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया गया।

5. हमने पक्षों के वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का अवलोकन किया है, जिसमें अपील के तहत आने वाले उच्च न्यायालय के आदेश और समेकन अधिकारियों द्वारा पारित तीन आदेशों

के अलावा यू.पी.जेड.ए. की धारा 209 के तहत मुकदमे में पारित पहले के आदेश भी शामिल हैं। एवं एल.आर. अधिनियम और उससे उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही, हमने पाया कि उच्च न्यायालय ने यू.पी.जेड.ए. की धारा 210 के प्रावधान पर ध्यान दिया एवं एल.आर. अधिनियम जो इस प्रकार पढ़ता है।

> "धारा 209 के तहत मुकदमा दायर करने में विफलता के परिणाम। यदि धारा 209 के तहत किसी भी भूमि से बेदखली का मुकदमा भूमिदार या असमी द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, या ऐसे किसी भी मुकदमे में प्राप्त बेदखली के लिए डिक्री प्रदान की गई सीमा अवधि के भीतर निष्पादित नहीं की जाती है ऐसे मुकदमे की स्थापना या ऐसी डिक्री के निष्पादन के लिए, जैसा भी मामला हो, कब्जा लेने या बनाए रखने वाला व्यक्ति।
>
> (क) जहां भूमि हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिदार की जोत का हिस्सा है, ऐसी भूमि के हस्तांतरणीय अधिकार वाले भूमिदार बन जाएंगे और ऐसी भूमि में असामी का अधिकार और हित, यदि कोई हो, समाप्त हो जाएगा।"

उच्च न्यायालय ने सही ढंग से देखा कि यदि यू.पी.जेड.ए. की धारा 209 के तहत एक मुकदमे में प्राप्त डिक्री धारक को दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है एवं एल.आर. अधिनियम को अपने अधिकार

खोने होंगे; पहला, वह सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर डिक्री को निष्पादित करने में विफल होना चाहिए और दूसरा, व्यक्ति (प्रतिकूल अधिकारों का दावा करने वाला) विवादित भूमि पर कब्ज़ा कर ले या बनाए रखे। इस प्रकार कानून की आवश्यकता पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया जो उसके विचार के लिए उठा:

> "दो रिट याचिकाओं में निर्णय के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं ने प्रतिकूल कब्जे से अधिकार हासिल कर लिया है और पी.जेड.ए. और एल.आर.एक्ट की धारा 210 के आधार पर सरदार बन गए हैं, इस आधार पर कि पहले के मुकदमे में पारित बेदखली की डिक्री निष्पादित नहीं की गई थी और परिसीमा द्वारा वर्जित मानकर खारिज कर दिया गया। यू.पी.जेड.ए. का धारा 210 और एल.आर.एक्ट इस प्रकार है।"

इसके बाद मुख्य रूप से इस तथ्य पर भरोसा करते हुए उत्तरदाताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं) के पक्ष में सवाल का जवाब दिया गया कि डिक्री धारकों (श्रीमती राम मूर्ति देवी और उनकी बहनों) द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

6. हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री की पुष्टि किए जाने के बाद निर्णय-देनदारों

(वर्तमान उत्तरदाताओं) ने स्वेच्छा से विवादित भूखंडों का कब्जा डिक्री धारकों को सौंप दिया था और निष्पादन की वस्तु खड़ी हो गई थी पूरा किया गया और यही कारण था कि डिक्री को समय पर क्रियान्वित नहीं किया गया और उसे कालबाधित होने दिया गया, उच्च न्यायालय ने बिना किसी उचित विचार के विवाद को खारिज कर दिया। इस संबंध में, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

> "यहां तक कि यह तथ्य समेकन प्राधिकारियों के समक्ष पार्टियों की दलीलों में भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दलील पहली बार रिट याचिका में उठाई गई है और इसे प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। किसी के अभाव में यह दिखाने के लिए सामग्री कि ऐसी याचिका कभी निचली अदालतों के समक्ष उठाई गई थी, प्रतिवादी को रिट याचिका में पहली बार मामले के तथ्यात्मक पहलू को छूते हुए एक नई याचिका उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

इसे आगे इस प्रकार देखा गया:

> "यह स्थापित करने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव में कि श्रीमती राम मूर्ति देवी और अन्य जो अली हसन के विक्रेता हैं, ने बेदखली के आदेश के बाद विवादित भूखंडों पर कब्जा कर लिया। यू.पी.जेड.ए. और एल.आर. अधिनियम की धारा 210 के

प्रावधान लागू हैं पूरी ताकत के साथ बेदखली के आदेश को क्रियान्वित नहीं किया जा सका और समय बाधित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस प्रकार विवादग्रस्त भूखंड में श्रीमती राम मूर्ति देवी और अन्य का अधिकार समाप्त हो गया। एक बार विवादग्रस्त भूखंडों पर उनका कोई अधिकार नहीं रह गया था, किसी भी बिक्री के बल पर अली हसन के पक्ष में कोई अधिकार अर्जित नहीं होगा उनके द्वारा निष्पादित विलेख इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने यू.पी.जेड.ए. एवं एल.आर.एक्ट की धारा 210 के अनुसार अपने अधिकारों को पूरा किया।"

हमें डर है कि उच्च न्यायालय ने उपरोक्त उद्धृत टिप्पणियाँ करने और अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई याचिका पर उचित विचार नहीं करने में गंभीर गलती की है। हमने पाया कि चकबंदी अधिकारी का आदेश पूरी तरह से विवादित भूखंडों पर प्रतिद्वंद्वी पक्षों के कब्जे के मुद्दे पर आधारित है। यह मुद्दा न केवल चकबंदी अधिकारियों के समक्ष उठाया गया बल्कि यह विवाद की जड़ बन गया। दोनों पक्षों ने विवादित भूखंडों पर कब्जे के अपने दावे के संबंध में दस्तावेजों सबूत पेश किए और चकबंदी अधिकारी ने उनके समक्ष पेश की गई सामग्रियों की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि उत्तरदाता विवादित भूखंड पर अपने निरंतर कब्जे को साबित करने में असमर्थ थे। 12 वर्षों के लिए भूमि और इसके विपरीत, अपीलकर्ता ही

विवादित भूखंडों पर कब्ज़ा कर रहा था। चकबंदी अधिकारी के आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

"वादी की ओर से, भूमि राजस्व रसीद दायर की गई है, जो न तो वादी को सरदार और न ही भूमिदार साबित करती है। इसके खिलाफ, प्रतिवादी की ओर से, हम वर्षों के खसरा के उद्धरण की प्रतिलिपि: 1368 एफ से 1380 एफ, खसरा 1378 एफ, 1380 एफ, 1370 एफ, 1371 एफ, 1372 एफ, 1373 एफ, 1374 एफ, 1375 एफ, 1376 एफ, 1377 एफ का उद्धरण दाखिल किया गया है, जिससे पता चलता है कि लगातार 12 वर्षों तक विवादित भूमि पर वादी, गंगू सिंह और अन्य का कब्जा साबित नहीं हुआ है। इसके विपरीत प्रतिवादियों को खाता नंबर 9 के भूमिदार या विवादित भूखंड दर्ज हैं, प्रतिवादी अली हसन का नाम प्रतिवादी राम मूर्ति और अन्य द्वारा निष्पादित बिक्री पत्र दिनांक 13.4.70 के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसके खिलाफ नंबर है वादी गंगू सिंह और अन्य के साक्ष्य, जो गंगू सिंह और अन्य के पक्ष में विवादित भूमि पर भूमिदार अधिकार प्रदान कर सकते हैं। अपने मामले के समर्थन में, गंगू सिंह ने अपना बयान दर्ज किया है, लेकिन अपने कब्जा को साबित करने के लिए कोई अन्य स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया। अत: इस प्रकार वादी अपने 12 वर्षों से जारी अनाधिकृत कब्जे को

सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। अत: वादी विवादित भूमि का भूमिदार साबित नहीं हो सका है। प्रतिवादी राम मूर्ति एवं अन्य को विवादित खाता संख्या 65 का भूमिदार तथा प्रतिवादी अली हसन को विवादित खाता संख्या 9 वाद संख्या का भूमिदार सिद्ध किया गया है। 1 और 2 तदनुसार तय किए गए हैं।"

चकबंदी अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कब्जे का निष्कर्ष विवाद के लिए निर्णायक था और उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को नजरअंदाज करने में गलती की और यह माना कि उत्तरदाताओं को केवल इसलिए कब्जा माना जाएगा क्योंकि श्रीमती राम मूर्ति देवी द्वारा निष्पादन आवेदन दायर किया गया था और अन्य डिक्री धारकों को समयबाधित होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था।

7. उपरोक्त की गई चर्चाओं के आलोक में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश काफी अस्थिर है। हम तदनुसार उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हैं और चकबंदी उप निदेशक एवं चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को पुनः स्थापित करते हैं। अपील की अनुमति है लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

बी.बी.बी. अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शुभम अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।